भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 823

दिनांक 07 फरवरी, 2023 के लिए प्रश्न

राष्ट्रीय डेयरी विकास योजना

823. श्री अर्जुन लाल मीणा:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा स्वच्छ दुग्ध उत्पादन कार्यक्रम योजना और राष्ट्रीय डेयरी विकास योजना के उन्नयन के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ख) राष्ट्रीय पशुधन मिशन, चारा और पशु-चारा विकास संबंधी उप-मिशन के अंतर्गत उक्त योजनाओं को स्वीकृति दिए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) डेयरी परियोजना को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किसानों को क्या सुविधाएं प्रदान की गई हैं; और

(घ) उदयपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय डेयरी विकास योजना और नाबार्ड योजना के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों के किसानों और निवासियों के कल्याण और उत्थान के लिए अब तक किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री परशोत्तम रूपाला)

(क) और (ख) राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी) फरवरी 2014 में तीन मौजूदा योजनाओं नामतः गहन डेयरी विकास कार्यक्रम, गुणवत्तापूर्ण और स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण तथा सहकारी समितियों को सहायता का विलय करके शुरू किया गया था। जुलाई 2021 में, एनपीडीडी को दूध और दूध उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ाने और संगठित खरीद, प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और विपणन की हिस्सेदारी बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक कार्यान्वयन हेतु पुनर्गठित किया गया है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन, आहार और चारा विकास संबंधी उप-मिशन एक अलग योजना है, जिसका उद्देश्य आहार और चारे की उपलब्धता बढ़ाना है।

(ग) राज्य सरकार के प्रयासों को और संपूरित करने हेतु पशुपालन और डेयरी विभाग निम्नलिखित डेयरी विकास योजनाओं को लागू कर रहा है: -

i. राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम

ii. डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि

iii. डेयरी कार्यकलापों में लगी डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को सहायता

उपरोक्त योजनाओं से डेयरी क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर किसानों सहित किसान-सदस्यों को लाभ मिलता है।

(घ) एनपीडीडी योजना के अन्तर्गत उदयपुर (उदयपुर दूध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड) में 1278.67 लाख रुपए की कुल परियोजना लागत से दो परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है। इसमें केंद्रीय हिस्सा 957.32 लाख रुपए है तथा इसमें से 957.32 लाख रू. की राशि जारी की जा चुकी है। परियोजना ने अतिरिक्त 50 हजार लीटर दूध प्रसंस्करण क्षमता के सृजन, 115 स्वचालित दूध संग्रह इकाइयों और 114 इलेक्ट्रॉनिक दूध मिलावट परीक्षण मशीनों की स्थापना हेतु सहायता प्रदान की है।

उपरोक्त के अलावा, डेयरी उद्यमिता विकास योजना (डीईडीएस) और राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) योजनाओं के तहत नाबार्ड के माध्यम से सब्सिडी दी गई थी। उदयपुर जिले में इन योजनाओं के तहत नाबार्ड द्वारा जारी की गई सब्सिडी का विवरण निम्नानुसार है (एनश्योर पोर्टल पर सब्सिडी जारी करने की प्रक्रिया के डिजिटलीकरण के बाद):-

योजना का नाम	**लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या**	**जारी की गई सब्सिडी की राशि (₹ लाख)**
डेयरी उद्यमिता विकास योजना (डीईडीएस)	202	96.80*
राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम)	3	22.89#

* सितंबर 2017 के बाद; # दिसंबर 2018 के बाद

****